www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 43 | जौनपुर, सोमवार, 28 सितम्बर 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

ज्ञानेश कुमार को हटाए बिना लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगे – हुसैन दलवई

मुंबई, (एजेंसी)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के काम करने के तरीके को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू का यह स्वीकार करना कि उनके मतभेद थे, इस बात को सिद्ध करता है कि आयोग के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग अमित शाह और पीएम मोदी के इशारे पर काम कर रहा है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है और इसे तुरंत बदलना चाहिए ।कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा, ष्ज्ञानेश कुमार कहीं न कहीं खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। चुनाव आयोग 3 लोगों का कमीशन है और तीनों को बराबर अधिकार हैं, लेकिन वह दोनों को साइडलाइन करके रखते हैं। दोनों सदस्यों–विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि हमारे मतभेद थे, वो मिट गए। मतलब मतभेद थे, ये तो सिद्ध हो गया न। मतभेद क्या है? जिस तरह से काम करते हैं– अमित शाह बोलते हैं, पीएम मोदी बोलते हैं, वैसे ही काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसे बदलना चाहिए ।ष्उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को हटाने के बाद ही इस देश में लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे। यह लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है, इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खराब करने का काम हो रहा है, जो बिल्कुल गलत

मंत्री आधव अर्जुन ने डीएमके पर साधा निशाना, लगाए गंभीर आरोप

चेंगलपट्टू, (एजेंसी)। तमिलनाडु सरकार में कैबिनेट मंत्री आधव अर्जुन (चुनाव प्रबंधन प्रभारी) और राजमोहन ने मदुरंथकम विधानसभा उपचुनाव में तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के उम्मीदवार मरगथम कुमारवेल के समर्थन में प्रचार किया। टीवीके की प्रचार सभा में बोलते हुए मंत्री आदव अर्जुन ने डीएमके सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि शुरुआत में वे आशंकाओं के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे, और उन्हें यह भी संदेह था कि क्या वे नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे, मतदान केंद्रों तक पहुंच पाएंगे, या डीएमके जैसी अपार वित्तीय और बाहुबल वाली पार्टी के खिलाफ खड़े हो पाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय ताकत की कमी के बावजूद, माताओं, बहनों और आम जनता द्वारा डाले गए वोटों की बदौलत उन्हें जीत मिली है ।उन्होंने कहा कि जनता ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि डीएमके को विपक्ष की बेंचों पर बैठना पड़ेगा। उन्होंने आगे बताया कि उनके विरोधियों ने उन्हें कम आंका था, यह सोचकर कि वे केवल सीटी बजाने में सक्षम हैं। अंततः, वही सीटी उनकी पार्टी का प्रतीक बन गई, और उन्होंने विपक्ष पर निर्णायक रूप से श्सीटी बजाकरश पलटवार किया।

अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन के चार पुरुषार्थों का आधार - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक प्राचीन संस्कृत सुभाषित साझा कर अच्छे स्वास्थ्य का संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य आधार उत्तम स्वास्थ्य ही है। इसका हिंदी अर्थ है कि तेजस्वी महर्षियों ने सुखपूर्वक बैठकर पुण्यमयी कथा का वर्णन किया। उनके अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकृजीवन के इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति का उत्तम मूल अच्छा स्वास्थ्य है। किसी शांत और पवित्र स्थान पर एकत्र होकर मानव जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य और

उसकी पहली शर्त पर विचार करते हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जीवन के चार मुख्य लक्ष्य माना गया है। श्लोक का भावार्थ स्पष्ट है कि यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो इनमें से कोई भी लक्ष्य सही ढंग से हासिल नहीं किया जा सकता। अस्वस्थ शरीर के साथ धर्म के कार्य कठिन हो जाते हैं, अर्थ अर्जित करना मुश्किल होता है, भौतिक सुखों का आनंद नहीं लिया जा सकता और मोक्ष की साधना भी असंभव हो जाती है। स्वास्थ्य वह पहली सीढ़ी और मजबूत जड़ है, जिस पर टिककर व्यक्ति अपने जीवन के सभी बड़े उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। पीएम मोदी के इस संदेश ने आयुर्वेद की प्राचीन ज्ञान परंपरा को एक बार फिर लोगों के सामने ला दिया है।

25 करोड़ लोगों को ईएसआईसी के जरिए स्वास्थ्य सुरक्षा दे रही सरकार – मनसुख मंडाविया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को कहा कि भारत 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम' (ईएसआईसी) के जरिए 25 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा दे रहा है। उन्होंने सरकार के सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों का भी जिक्र किया। 'औद्योगिक संबंध और श्रम एवं पुरस्कार 2026' पर सीआईआई–ईएफआई राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए, मंडाविया ने कहा कि सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ किसानों को हर चार महीने में उनके बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपए मिलते हैं। मंत्री ने कहा, "आज देश में 10 ऐसे राज्य हैं जो महिलाओं के खातों में हर महीने 2,000 रुपए, 1,500 रुपए या 1,200 रुपए जैसी रकम जमा करते हैं।" केंद्रीय मंत्री ने औद्योगिक संबंधों और अंतरराष्ट्रीय श्रम तौर–तरीकों एवं भारत की अपनी परंपराओं और प्रणालियों के बीच संतुलन पर बात करते हुए कहा, "जब हम औद्योगिक संबंधों

की बात करते हैं३ तो एक तरफ आईएलओ के अंतरराष्ट्रीय तौर–तरीके और अंतरराष्ट्रीय ढांचे होते हैं, और दूसरी तरफ भारत की अपनी परंपराएं और संबंधय तो मुझे यह थोड़ा अलग लगता है।" मांडविया ने कहा कि पिछले 10–11 वर्षों में कई मंत्रालयों में मंत्री के तौर पर काम करने के उनके अनुभव ने उन्हें भारत और विदेशों में विभिन्न मंचों और हितधारकों के साथ जुड़ने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संबंधों के प्रति भारत के दृष्टिकोण में अंतरराष्ट्रीय ढांचे और देश के अपने सामाजिक और आर्थिक संदर्भ, दोनों को ध्यान में रखने की जरूरत है। इससे पहले सितंबर में, मंत्री ने राज्य सरकारों से कहा था।

एआईआईबी की बैठक में भाग लेने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण कतर पहुंचीं

नई दिल्ली, (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की 11वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए कतर पहुंच गई हैं। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में सोमवार को दी गई। दोहा के हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कतर में भारत के राजदूत श्रीकर रेड्डी कोप्पुला ने उनका स्वागत किया। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "केंद्रीय वित्त मंत्री अगले दो दिनों के दौरान दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की 11वीं वार्षिक बैठक और

एआईआईबी इन्वेस्टर्स डायलॉग 2026 में भाग लेंगी।" वह एआईआईबी के अध्यक्ष के साथ–साथ जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब और नेपाल के अपने समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। वित्त मंत्री एआईआईबी में भारत के गवर्नर के रूप में बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। भारत एआईआईबी का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। आधिकारिक यात्रा के दौरान वित्त मंत्री कतर सरकार के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा, वह कतर के कारोबारी नेताओं और निवेशकों के साथ भी बातचीत करेंगी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जो एशिया और दुनिया भर में आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में सुधार के लिए सड़कों, स्वच्छ ऊर्जा और जल प्रणालियों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए वित्त पोषण करता है। बीजिंग में मुख्यालय वाले इस बैंक ने जनवरी 2016 में 100 अरब डॉलर की पूंजी के साथ काम शुरू किया था।

देश की पहली एलएनजी ट्रेन को हरी झंडी देंगे अमित शाह

अहमदाबाद, (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को साबरमती स्टेशन से देश की पहली एलएनजी संचालित ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। यह भारतीय रेल की किफायती रेल परिचालन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है ।यह पहल भारतीय रेलवे में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने तथा पारंपरिक डीजल ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।भारतीय रेलवे में पहली बार ट्रेन के ड्राइविंग पावर कार (डीपीसी) में लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) आधारित फ्यूल प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया गया है। इस तकनीक के माध्यम से एक ही इंजन में एलएनजी और डीजल दोनों ईंधनों का उपयोग किया जा सकता है। तेल और गैस

इस परियोजना के अंतर्गत 1400 एचपी क्षमता वाले दो ड्राइविंग पावर कार (डीपीसी) को एलएनजी ड्यूल–फ्यूल प्रणाली में परिवर्तित किया गया है। दोनों परिवर्तित डीपीसी पर 2,000 किलोमीटर से अधिक का सफल फील्ड ट्रायल पूरा किया जा चुका है। ट्रायल के दौरान तकनीक के प्रदर्शन एवं विश्वसनीयता का परीक्षण किया गया। एलएनजी ड्यूल–फ्यूल प्रणाली के उपयोग से डीजल की खपत में कमी के साथ–साथ आयात के खर्चे में भी कमी आने की संभावना है। इसकी लागत डीजल की तुलना में कम होने के कारण डीजल के स्थान पर एलएनजी के आंशिक उपयोग से परिचालन लागत में भी बचत होगी। परीक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लगभग 25 लाख रुपए प्रति डीपीसी प्रति वर्ष की बचत होने का अनुमान है। इस प्रकार एलएनजी आधारित फ्यूल प्रणाली, तकनीकी लाभ के साथ–साथ रेलवे के परिचालन व्यय को कम करने में भी सहायक होगी ।ड्यूल–फ्यूल प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि ईंधन की उपलब्धता के अनुसार इंजन डीजल और एलएनजी के बीच सहज रूप से स्विच कर सकता है। इससे ईंधन की उपलब्धता में किसी प्रकार की समस्या होने पर भी ट्रेन संचालन प्रभावित नहीं होता और परिचालन में दो ऑप्शन मिलते है एलएनजी एक बार ट्रेन में भरने के बाद ज्यादा किमी की दूरी तक जा सकता है। रेल से सामान भेजने की सेवा एलएनजी ड्यूल–फ्यूल प्रणाली को इस प्रकार डिजाइन किया गया है ।

धरपुरम में गरजेंगे सीएम विजय, सत्यबामा के लिए 30 सितंबर को करेंगे प्रचार

धरपुरम, (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेट्ट्री कजगम (टीवीके) के अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय 30 सितंबर को धरपुरम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में वे 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की उम्मीदवार पी. सत्यबामा के लिए प्रचार करेंगे ।टीवीके पदाधिकारियों ने बताया कि चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में प्रवेश करते ही मुख्यमंत्री विजय 4 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र में रोड शो भी करेंगे। टीवीके कार्यकर्ताओं ने जनसभा के लिए धरपुरम–उदुमलाई मार्ग पर 34 एकड़ जमीन का चयन किया है, जहां मंच और ध्वजदंड लगाने का काम चल रहा है। सभा के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही

है। पार्टी अधिकारियों ने बताया कि मंत्री केए सेंगोत्तैयान और अरुणकुमार टीवीके के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ विधानसभा क्षेत्र में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तिरुप्पुर जिले का धरपुरम तमिलनाडु विधानसभा की उन दो सीटों में से एक है जहां 6 अक्टूबर को मतदान होगा ।दूसरी सीट चेंगलपट्टू जिले का मदुरंतकम है। दोनों विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। उपचुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता सक्रिय हैं और पार्टियां अपना प्रचार अभियान तेज कर रही हैं। टीवीके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रचार विवरण के अनुसार, धरपुरम में 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, नाम तमिलर काची (एनटीके) के मुख्य समन्वयक सीमान और वामपंथी दलों के नेताओं के भी प्रचार में शामिल होने की उम्मीद है ।सत्यबामा ने अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके की ओर से धरपुरम सीट जीती थी, लेकिन बाद में पार्टी छोड़कर टीवीके में शामिल हो गईं। सत्ताधारी टीवीके ने उन्हें उपचुनाव में फिर से उम्मीदवार बनाया है।

कांति नगर मुहल्ले मे अवैध प्लॉटिंग और सड़क-नाली पर कब्जे के चलते रहता है जल भराव

लोगो ने सचिव विकास प्राधिकरण व नगर आयुक्त को पत्र देकर किया जांच की मांग

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या ।अयोध्या नगर निगम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के कांति नगर में कथित अवैध प्लॉटिंग और सड़क–नाली पर कब्जे को लेकर मोहल्ले के लोगो ने सचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण तथा नगर आयुक्त को शिकायती पत्र देकर जांच की मांग की है ।लोगो का कहना है अवैध कब्जी के चलते नाली का पानी आसपास बह रहा है और बारिश में सबसे बुरा हाल हो जाता है लोगों का कहना है यहां पर लगभग 250 से अधिक की आबादी है और सभी लोग इस गंभीर समस्या से परेशान हैं। मोहल्ले वासियों ने शिकायती पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि एक तो यहां पर अवैध प्लाटिंग हो रही है ऊपर से यहां पर गंदगी है और यहां के स्थानीय पार्षद कभी भी दिखाई नहीं पड़ते हैं ।शिकायत पत्र मे लोगो ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों द्वारा ऐसी भूमि की प्लॉटिंग कर बिक्री की गई है,जो अवैध है ।वही प्लॉट खरीदने के बाद कुछ स्थानों पर सड़क और नाली को तोड़कर कब्जा किए जाने तथा बाउंड्रीवाल व मकान निर्माण का काम किया जा रहा है। जिसके चलते हल्की सी बारिश में जल भराव बना रहता है ।कुछ भवनों का नक्शा संबंधित प्राधिकरण से स्वीकृत कराए बिना

निर्माण कराया जा रहा है ।वही निर्माण सामग्री सड़क पर गिरने से आवागमन प्रभावित होने की बात भी शिकायत में कही गई है ।इससे पैदल चलने और वाहनों के आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अपराधियों पर शिकंजा कसना तथा फरियादियों को त्वरित न्याय प्रदान करना नवागत एसपी ग्रामीण की प्रथम प्राथमिकता

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। क्षेत्र मे अपराध नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था कायम रखना नवागत एसपी ग्रामीण राधेश्याम राय की प्रमुख प्राथमिकता है ।उन्होंने बताया कि आगामी दुर्गा पूजा,रामलीला व अन्य पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराना है ।बताया कि पर्व कोई भी हो उसे हम सभी को भाईचारे के साथ मनाना चाहिए ।कहा कि अपराध नियंत्रण के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के साथ–साथ उनके समस्याओं को त्वरित निस्तारण किया जाएगा ।वही पुलिस और जनता के बीच आपसी बेहतर समन्वय हो इसके लिए बीच–बीच में थाना क्षेत्र में बैठक भी किया जाएगा ।जिससे लोगों का पुलिस पर भरोसा भी मजबूत होगा ।बदलते समय में साइबर अपराध, धोखाधड़ी और संगठित आपराधिक गतिविधियां पुलिस के सामने नई चुनौतियां पेश कर रही हैं ।ऐसे में तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल, खुफिया सूचनाओं के संकलन और पुलिसकर्मियों की सक्रियता से अपराधियों पर शिकंजा कसना महत्वपूर्ण हो गया है। वहीअपराधियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी ।सक्रिय अपराधियों, वांछित आरोपियों और आपराधिक

गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के दायरे में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी ।पुलिस की सक्रियता का उद्देश्य अपराध होने के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं,बल्कि अपराध की रोकथाम भी है।

परंपरागत चिकित्सा का आधुनिक रूप, आयुर महोत्सव में सूर्य शिरोधारा की पहल

ब्यूरो चीफ
सत्य प्रकाश उपाध्याय

नोएडा। सेक्टर–62 स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में चल रहे आयुर महोत्सव 2026 में आयुर्वेद की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने वाली कई पहल देखने को मिल रही हैं। इसी क्रम में एज आयुर्वेद की ओर से पेश किया गया पोर्टेबल सूर्य शिरोधारा उपकरण लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना। कंपनी के प्रतिनिधि धनंजय शर्मा ने बताया कि सूर्य शिरोधारा को पारंपरिक शिरोधारा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से विकसित किया

गया है। उपकरण में शिरोधारा की मूल प्रक्रिया और आयुर्वेदिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का विस्तार वैश्विक स्तर पर तेजी से हो रहा है, लेकिन इसके साथ इसकी प्रामाणिकता, गुणवत्ता और मूल चिकित्सकीय सिद्धांतों को बनाए रखना भी जरूरी है। आधुनिक तकनीक का उपयोग आयुर्वेद को अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है। महोत्सव के दौरान आयुर्वेदिक उत्पादों, उपचार पद्धतियों और नई तकनीकों को लेकर चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों के बीच संवाद भी हुआ। एज आयुर्वेद ने बताया कि उसके उत्पाद देश के विभिन्न हिस्सों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रहे हैं। कंपनी का लक्ष्य पारंपरिक आयुर्वेद को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़कर इसे व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराना है।

संपादकीय

विश्व जनमत की स्वीकृति

भारत के अभिन्न अंगों को आधिकारिक भारतीय मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए, इस रुख से देश को आश्वस्त करने के बाद सरकार को यह बताना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र इस भावना के खिलाफ क्यों गया? सोलहवीं सदी से इस्तेमाल हो रहे मर्केटर मानचित्र को बदलने के प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र में समर्थन कर भारत ने उचित रुख अपनाया। पुराना नक्शा जाहिरा तौर पर औपनिवेशिक नजरिए से तैयार किया गया था, जिसे बदलना विश्व बहुमत की जीत समझा जाएगा। यह बात संयुक्त राष्ट्र में हुए मतदान में भी जाहिर हुई, जहां सिर्फ अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। आम तौर पर उसके पीछे चलने वाले छह देशों ने तटस्थ रुख अपनाया, जबकि भारत सहित 164 देशों ने मानचित्र बदलने का समर्थन किया। अतरू बाद में जो हुआ, उसे नए नक्शे के समर्थन के भारत सरकार के फैसले से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह बेशक गहरे अफसोस की बात है कि बाद में संयुक्त राष्ट्र ने जो विश्व मानचित्र जारी किया, उसमें भारत की प्रादेशिक अखंडता का ख्याल नहीं रखा गया। इसमें जम्मू–कश्मीर, लद्दाख, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान और चीन के साथ विवादित हिस्से के रूप में दिखाया गया है। उचित ही भारत सरकार ने उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उसने स्पष्ट कहा है कि ऐसा कोई भी चित्रण, जो आधिकारिक भारतीय नक्शे से मेल नहीं खाता, वह पूर्णतरू अमान्य और अस्वीकार्य है। भारतीय विदेश मंत्रालय दो–टूक कहा है कि भारत की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। भारत के अभिन्न अंगों को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। बहरहाल, इस रुख से देश को आश्वस्त करने के बाद भारत सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र इस भावना के खिलाफ क्यों गया? भारत के जिन इलाकों पर पाकिस्तान और चीन की निगाहें रही हैं, आखिर उनके बारे में विश्व समुदाय का बहुमत क्या सोचता है? हालांकि किसी बाहरी ताकत की सोच अपनी प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करने के भारतीय आवाम के इरादे को नहीं डिगा सकती, फिर भी दुनिया में सम्मानित राष्ट्र के रूप खड़े रहने के लिए अपने पक्ष को विश्व जनमत की स्वीकृति दिलाना भी अनिवार्य है। इस बिंदु पर दुनिया में भारत की क्या स्थिति है, इस बारे में देशवासियों को भरोसे में लिया जाना चाहिए।

राजनीतिक क्षेत्र में दूर की कोड़ी है लैंगिक समानता

डॉ. राजेन्द्र

विश्व आर्थिक मंच डब्बूईएफ द्वारा इसी 16 सितंबर, 2026 को जारी 20 वीं ग्लोबल जेंडर लैंगिक गैप रिपोर्ट 2026 से एक बात तो साफ हो गई है कि राजनीति में अभी तो सत्ता में महिलाओं की पुरुषों के समान भागीदार दूर की कोड़ी ही है। जेंडर गैप की हालिया रिपोर्ट में सबसे रौचक और चिंताजनक जानकारी यह सामने आई है कि संसद में भले ही महिलाओं की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत हो गई हो पर मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी केवल 5.9 प्रतिशत रह गई है। सबसे मजे की बात यह है कि 2019 की तुलना में मंत्रिमंडल में महिलाओं की उच्चतम स्तर 30 प्रतिशत की भागीदारी की तुलना में बहुत कम हो गई है। यह सब तो तब है जब केन्द्र सरकार 2023 में महिला आरक्षण बिल लेकर आई है। हांलाकि यह भी अभी तो राजनीति की भेंट ही चढ़ा हुआ है। यह इसलिए भी एलार्मिंग हो जाती है कि लैंगिक समानता की बात दुनिया के देशों द्वारा विभिन्न मंचों पर बढ़–चढ़ कर कितनी भी की जाएं परिणाम अभी तक अधिक सकारात्मक प्राप्त नहीं हुए हैं। आइसलैंड, फिनलैंड, नार्वे आदि अवश्य लैंगिक गैप को कम करने में कुछ हद तक सफल रहे हैं। निराश होने की बात इसलिए नहीं है कि शिक्षा–स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में लैंगिक गैप में लगातार सुधार देखा जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी महिलाओं की हिस्सेदारी में सुधार देखा जा रहा है। विश्व आर्थिक मंच या यों कहें कि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई और 2006 से डब्बूईएफ ने दुनिया के देशों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर जेंडर लैंगिक गैप का सालाना सर्वे करना शुरु किया। 145 देशों में कराये गये हालिया सर्वे की रिपोर्ट में भारत की रेंक 131 वीं है। हांलाकि बीस सालों में रेंक में सुधार हुआ है। संस्था द्वारा जेंडर लैंगिक स्थिति का अध्ययन के लिए चार मानक बनाए हुए हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सरवाइवल, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं भागीदारी और राजनीति सशक्तिकरण चार ऐसे क्षेत्र है जिनके माध्यम से दुनिया के देशों में महिलाओं की वैश्विक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। जहां तक भारत की बात है देखा जाएं तो जेंडर लैंगिक गैप की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य व सरवाइवल के क्षेत्र में भारत में स्थिति बेहतर है। शिक्षा के क्षेत्र में यह 96.6 प्रतिशत और स्वास्थ्य और उत्तरजीवितता में 95.6 प्रतिशत का आंकड़ा है। इसे निश्चित रुप से सकारात्मक माना जाता है। इसका साफ साफ अर्थ यह हो जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य व सरवाइवल क्षेत्र में लैंगिक गैप में सकारात्मकता है और महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर को लगभग पाट सा दिया है। जहां तक महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी की बात है तो इसमें समग्र रुप से 41.2 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। यानी अभी भी लैंगिक गैप का अंतर 50 फीसदी से भी अधिक बना हुआ है। हांलाकि आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में लगातार सुधार देखा जा रहा है। कुल कामकाजी महिलाओं की हिस्सेदारी 39.9 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 42 फीसदी हो गई है। आर्थिक मोर्चे पर लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है पर जिस तेजी से बढ़ोतरी होनी चाहिए थी या जिस तरह से लैंगिक गैप कम होना चाहिए था वह अभी नहीं हो पाया है। तस्वीर का सबसे निराशाजनक पहलू राजनीतिक भागीदारी को लेकर हैं। खासतौर से मंत्रीमण्डल में तो महिलाओं की हिस्सेदारी में बहुत अधिक कमी देखने को मिल रही है। यह सब तो तब है जब सरकार राजनीति में महिला आरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाने की पक्षधर है। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि पिछले कुछ सालों के चुनावों पर नजर ड़ाली जाएं चाहे वे विधानसभाओं के हो या लोकसभा के सभी में मतदान से लेकर सरकार बनवाने में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। कम से कम आंकड़े तो यही कह रहे हैं। हांलाकि फ्री बीज जैसी लुभावनी योजनाओं में महिलाओं को अपने पक्ष में करने के वादे सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में देखने को मिल जाएगा। संतोष की बात यह है कि 145 देशों की समग्र ग्लोबल जेंडर गैप 2026 का जेंडर गैप पेरिटी स्कोर 69.2 प्रतिशत है जबकि भारत की 131 वीं रेंक होने के बावजूद इस रिपोर्ट में भारत का ग्लोबल जेंडर लैंगिक गैप पेरिटी स्कोर 64.5 प्रतिशत रहा है। रिपोर्ट के समग्र अध्ययन से यह साफ हो जाता है कि भारत के सामने सबसे अधिक चुनौती राजनीतिक स्तर पर गैप को कम करना है तो आर्थिक मोर्चे पर भी अभी बहुत कुछ किया जाना जरुरी हो गया है। देश में बेटी बचाओं–बेटी पढ़ाओं जैसे अभियानों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। पंचायतों, निकाओं आदि में महिलाओं के आरक्षण से राजनीति में जो भागीदारी देखी जा रही है वह संभव हो पाई हैं। निर्णय के स्तर पर भी महिलाएं अधिक स्वतंत्र हुई है और चुनाव नतीजे इस बात को पुष्ट भी करते हैं। अब महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग स्वविवेक से करने लगी है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 93 प्रतिशत के स्कोर के साथ आइसलैंड भले ही शीर्ष पर हो पर दुनिया के अधिकांश इस दौड़ में अभी बहुत पीछे हैं। शत–प्रतिशत स्कोर की तो अभी कल्पना करना बेमानी ही होगा। पर सकारात्मक पक्ष यह है कि लैंगिक गैप में अब काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र इसका बड़ा उदाहरण है। आर्थिक मोर्चों पर भी महिलाओं की भागीदारी भले ही कम हो पर शीर्ष स्तर पर भी महिलाओं की हिस्सेदारी देखी जा सकती है। इसलिए चुनौती अवश्य है पर हालात सकारात्मकता की और संकेत कर रहे हैं।

आम लोगों और सीबीआई निदेशक के साथ आखिर अलग अलग सलूक

नीरज

नई दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चल रही कवायद के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरी प्रक्रिया पर फिर से बहस तेज कर दी है। हम आपको बता दें कि जिन प्रमुख और चर्चित मतदाताओं के नाम पर एसआईआर के दौरान नोटिस जारी हुए थे, उनमें से अधिकांश के विवरण और दस्तावेजों का सत्यापन अब पूरा कर लिया गया है और उन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाने के लिए हरी झंडी मिल गई है। इनमें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे चर्चित नाम शामिल हैं। इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री, पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे अरविंद पनगढ़िया, भाजपा विधायक कैलाश गहलोत, पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग सहित कई अन्य प्रमुख लोगों को भी एसआईआर के दौरान नोटिस मिला था। चुनाव अधिकारियों के अनुसार इन मामलों की व्यक्तिगत रूप से जांच की गई और संबंधित मतदाताओं से आवश्यक जानकारी तथा दस्तावेज हासिल किए गए। सत्यापन पूरा होने के बाद इनके नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। दरअसल, इन चर्चित नामों को नोटिस मिलने के बाद सवाल उठने लगे थे कि आखिर ऐसे लोगों के नाम भी एसआईआर की जांच के दायरे में कैसे आ गए? चुनाव अधिकारियों का कहना है कि मतदाता विवरण में कुछ तार्किक विसंगतियां मिली थीं या फिर मौजूदा विवरण पिछली गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े अभिलेखों से मेल नहीं खा रहा था। इसी आधार पर संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों के मुताबिक नोटिस मिलना अपने आप में मतदाता सूची से नाम काटे जाने का संकेत नहीं है, बल्कि यह संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का अवसर देता है। लेकिन असली सवाल यहीं से पैदा होता है। दिल्ली में एसआईआर के तहत करीब 33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई है। यानी यह प्रक्रिया केवल कुछ चर्चित चेहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर लाखों आम मतदाताओं पर पड़ रहा है। नोटिस जारी होने के बाद आम मतदाता को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी पात्रता और विवरण साबित करने के लिए दस्तावेज जुटाने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ चर्चित और प्रभावशाली लोगों के मामलों में अधिकारियों द्वारा संपर्क कर दस्तावेज जुटाने और सत्यापन पूरा करने की प्रक्रिया सामने आई है। यही अंतर अब एसआईआर की पूरी कवायद के केंद्र में आ गया है। कुछ रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के एसआईआर में अधिकारियों के स्तर पर वीआईपी मतदाताओं की पहचान कर उनके सत्यापन के लिए अलग तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इन रिपोर्टों के अनुसार सामान्य मतदाताओं को जहां नोटिस के बाद सुनवाई और दस्तावेजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, वहीं प्रभावशाली मतदाताओं के मामलों में प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान रही। यह आरोप चुनावी प्रक्रिया की समानता और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि चुनाव अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष यह है कि नोटिस जारी करने का आधार मतदाता के पद या प्रतिष्ठा नहीं,

बल्कि एसआईआर के दौरान सामने आई विसंगतियां हैं और सभी मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि अंतिम मतदाता सूची चार नवंबर को प्रकाशित की जानी है, जबकि नोटिसों के निस्तारण की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक पूरी की जानी है। इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि जिन चर्चित मतदाताओं के नाम एसआईआर के दौरान सवालों के घेरे में आए, वे सत्यापन के बाद अंतिम सूची में जगह पाने की स्थिति में हैं। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि लाखों आम मतदाताओं के मामलों का निस्तारण किस गति और किस समान प्रक्रिया के तहत होता है और चार नवंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची एसआईआर को लेकर उठे सवालों का कितना स्पष्ट जवाब देती है। बहरहाल, इतना तो दिख ही रहा है कि चुनाव आयोग की ओर से आम और खास में फर्क किया जा रहा है।

बस्तर में बदलाव के वाहक पीएम मोदी

किरण सिंह देव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष सेवा, सुशासन और अंत्योदय के संकल्प की प्रेरक यात्रा है। लोक कल्याण की उनकी अहर्निश यात्रा अन्त्योदय को समर्पित है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित प्रत्येक नीति के केन्द्र में गरीब, किसान, महिला, युवा और विशेष रूप से जनजातीय समाज होता है। छत्तीसगढ़ के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विशेष आत्मीय जुड़ाव रहा है। श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी के जीवन स्तर को गुणवत्ता प्रदान की है।

इस बदलाव की सबसे सुन्दर तस्वीर बस्तर में दिखाई देती है। बस्तर प्राकृतिक सम्पदा, समृद्ध जनजातीय संस्कृति और मेहनतकश लोगों की धरती है। लम्बे समय तक नक्सल हिंसा के कारण इस क्षेत्र की संभावनाएँ पूरी तरह सामने नहीं आ पाईं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा और विकास को साथ लेकर चलने की नीति ने परिस्थितियाँ बदली हैं। आज जिन इलाकों में शासन–प्रशासन का पहुँचना कठिन था, वहाँ सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल, अस्पताल और सरकारी योजनाएँ पहुँच रही हैं। कनेक्टिविटी इस बदलाव का मजबूत आधार बनी है। बस्तर क्षेत्र में 3,240 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है और 889 मोबाइल टॉवर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 234 बसाहटों को जोड़ने के लिए 228 सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है।

सड़क केवल दो स्थानों को नहीं जोड़ती, वह लोगों को अवसरों से जोड़ती है। सड़क पहुँचती है तो बाजार पहुँचता है, एम्बुलेंस पहुँचती है, शिक्षक पहुँचते हैं और रोजगार के नए रास्ते खुलते हैं। जिन रास्तों पर कभी नक्सली बारूद बिछाते थे, आज उन्हीं रास्तों पर विकास की गाड़ी चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बस्तर तेसे आगे बढ़ रहा है। नक्सल हिंसा के कारण बंद पड़े 421 स्कूलों को फिर से खोला गया है। अबूझमाड़ और जगरगुण्डा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी विकसित करने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारा प्रयास है कि बस्तर के बच्चों को अपने क्षेत्र में ही अच्छी शिक्षा, आवासीय सुविधा और आगे बढ़ने का बेहतर वातावरण मिले। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बस्तर के सभी 32 विकासखण्डों में कौशल विकास केन्द्र प्रारम्भ किए गए हैं। बस्तर ओलम्पिक ने गाँव और जनजातीय अंचलों की खेल प्रतिभाओं को बड़ा मंच दिया है। बस्तर पण्डुम ने यहाँ की संस्कृति, लोककला, परम्परा और जनजातीय गौरव को नई पहचान दी है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर पण्डुम की सराहना करते हुए ऐसे आयोजनों को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और स्थानीय समुदायों के सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण बताया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बदलाव साफ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के अंतर्गत 34 लाख से अधिक स्वास्थ्य परीक्षण कर डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार की गई है। दूरस्थ क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से सेवाएँ पहुँचाई जा रही हैं। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू हुआ है और गीदम में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएँ समावेशी बनी हैं। हमारे वैचारिक अधिष्ठान के प्रणेता श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि राजनीति का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास होना चाहिए। देश के प्रधान सेवक नरेन्द्र मोदी ने अन्त्योदय की विचारधारा को साकार रूप दिया है। उनके विजन पर चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने नियद नेल्लानार योजना के जरिए बस्तर समेत छत्तीसगढ़ के सबसे दुर्गम गाँवों तक विकास का उजाला पहुँचाया है। सुरक्षा शिविरों के 10 किलोमीटर के दायरे के 525 गाँवों में शासन के 17 विभागों की 43 हितग्राहीमूलक और सामुदायिक योजनाओं के माध्यम से लोगों को सुविधाओं से जोड़ा गया।

एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी है कि सुरक्षा शिविरों को शहीद वीर गुण्डाधुर सेवा डेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन केन्द्रों से स्वास्थ्य, बैंकिंग, कृषि सहायता, कौशल विकास, आजीविका और दूसरी नागरिक सेवाएँ लोगों के नजदीक पहुँच रही हैं। छत्तीसगढ़ के विकास का अगला बड़ा आधार उसकी वन सम्पदा है। इमली, महुआ, सालबीज, चिरौंऔर अनेक वनौषधियाँ यहाँ के जनजातीय परिवारों की आजीविका से जुड़ी हैं। बस्तर और सरगुजा में कृषि एवं वन आधारित प्रसंस्करण इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बस्तर की दूसरी बड़ी ताकत पर्यटन है। चित्रकोट और तीरथगढ़ के जलप्रपात, कांगेर घाटी, घने जंगल, गुफाएँ और अनूठी जनजातीय संस्कृति इसे प्रकृति और संस्कृति आधारित पर्यटन के लिए विशिष्ट बनाते हैं। इको पर्यटन और स्थानीय होमस्टे को बढ़ावा देकर पर्यटन को स्थानीय परिवारों की आय और रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है।

27 सितम्बर विश्व नदी दिवस, नदियां बचेंगी तो बचेगा जीवन नदी संरक्षण की चुनौती

राज कुमार

भारत को नदियों का देश माना जाता है तथा यहां छोटी और बड़ी नदियों को मिलाकर लगभग 4000 से अधिक नदियां है। देश में 521 नदियों के पानी की निगरानी करने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश की 198 नदियां ही स्वच्छ हैं। इनमें अधिकांश छोटी नदियां हैं। शहरीकरण, औद्योगीकरण तथा

अनियोजित विकास के कारण पिछले कुछ दशकों से नदियों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक होती जा रही है। कई सहायक नदियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है।पृथ्वी पर नदियां जीवनदायिनी है। इसलिए अन्नजल देने वाली इन नदियों को मां मानकर पूजा जाता है। नदियों के बिना मानव जाति के विकास की परिकल्पना असंभव थी। नदियों ने मानव जाति के साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाकर मानव जाति के विकास में पूरा सहयोग किया। उसकी दैन्दिनी की हर जरूरत को पूरा किया। परंपरागत समय में मानवजाति ने नदियों के इस आत्मीय सहयोग को पूरा मान–सम्मान दिया किन्तु आज लोभ और लाभ की मनोवृत्ति की वजह से नदियां संकट में है। नदियों के विनाश में बाजारवाद का बढ़ता प्रभाव भी एक प्रमुख कारक है। पृथ्वी अब वैश्विक जल दिवालियापन के दौर में प्रवेश कर चुकी है। दुनिया के अनेक नदी घाटियों और जलभृतों (एक्विफर) में दीर्घकालिक जल उपयोग, प्राकृतिक पुनर्भरण और सुरक्षित दोहन की सीमाओं से कहीं अधिक हो चुका है। कई नदी घाटियों में कानूनी जल अधिकार, अनौपचारिक अपेक्षाएं और विकास संबंधी वादे, क्षरित जल–वहनीय क्षमता से कहीं अधिक हो चुका है, जबकि जल दिवालियापन से निपटने के लिए प्रभावी संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद नहीं है। जब कभी नदियों पर बात होती है तो ज्यादातर बड़ी नदियों पर केंद्रित होती है। लेकिन इन सदानीरा नदियों का भरपूर जल देने वाली छोटी नदियों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जो आज अभूतपूर्व संकट से गुजर रही हैं। इनमें से कई छोटी–बड़ी नदियां या तो सूख चुकी हैं या फिर बरसाती नाले बनकर रह गई हैं। अगर हमें बड़ी नदियों को बचाना है तो छोटी नदियों पर ध्यान देना होगा। छोटी नदियों का संरक्षण जरूरी है। भारत को नदियों का देश माना जाता है तथा यहां छोटी और बड़ी नदियों को मिलाकर लगभग 4000 से अधिक नदियां है। देश में 521 नदियों के पानी की निगरानी करने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश की 198 नदियां ही स्वच्छ हैं। इनमें अधिकांश छोटी नदियां हैं।शहरीकरण, औद्योगीकरण तथा अनियोजित विकास के कारण पिछले कुछ दशकों से नदियों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक होती जा रही है। कई सहायक नदियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। आईआईटी धनबाद संस्थान के पर्यावरण विज्ञान इंजिनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अंशुमाली और उनकी टीम ने शोध में खुलासा किया है कि पिछले 50 वर्षों में गंगा नदी की करीब 18 लाख जल धाराएं गायब हो गई है। उन्होंने झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में 7 छोटी नदियों और उनके 56 वाटर शेड्स का अध्ययन किया, जो गंगा में जाकर मिलती है। नदियों में प्रदूषण का असल खमियाजा तो कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। प्रदूषित नदियों के जल से सिंचाई होती है और इससे प्रदूषण उस कृषि भूमि पर पहुंच जाती है जहां से सीधे खाद्यान्न आता है। अब एक तरफ तो पैदावार बढ़ाने के लिए किसान खतरनाक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ प्रदूषित नदियों का जल उसे और अस्वास्थ्यकर बनाता है। दूसरी ओर रेत खनन से नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को कई तरह से नुकसान होता है, जिसमें नदी के तल का क्षरण, जलीय आवास का नष्ट होना, और जैव विविधता में कमी शामिल है। इससे नदी के प्रवाह और अवसादन पैटर्न में बदलाव आता है, जिससे बाढ़ और कटाव बढ़ता है। यह नदी के गंदलेपन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की मात्रा घटाता है, और भूजल स्तर को नीचे कर सकता है, जिससे स्थानीय पेयजल की कमी होती है। रेत खनन से नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, जिससे स्थानीय जीवों के जीवन को खतरा होता है। रेत खनन नदियों के इकोसिस्टम को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। इसके लिए अवैध रेत खनन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष निगरानी दल का गठन किया जाना चाहिए। अवैध खनन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए और उनके उपकरण जब्त किए जाएं। निर्माण कार्यों के लिए रेत के वैकल्पिक साधनों की खोज और उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। माइन्स एंड मिनरल रेगुलेशन एक्ट 1957 में प्रमुख और उपखनिज को परिभाषित किया है। 1957 से अब तक स्थिति बदल चुकी है और रेत का इस्तेमाल कई गुणा बढ़ गया है। रेत खनन के कारण पर्यावरण पर हो रहे असर की व्यापकता को देखते हुए इसे लघु नहीं, बल्कि प्रमुख खनिज में शामिल कर सख्त पर्यावरणीय अनुमति का प्रावधान किया जाना चाहिए। वर्तमान दौर में नदियां कम्पनियों, कॉर्पोरेट्स और सरकार के मुनाफा कमाने का साधन बन चुकी है। नदियों का प्रशासकीय प्रबंधन की जगह पर्यावरणीय प्रबंधन की दृष्टी से निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए। जिसमें पारिस्थितिकीय तंत्र, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की समझ रखने वाले विशेषज्ञ को शामिल किया जाना आवश्यक है। नदी पर बने बांधों से कई लाभ मिले हैं, वहीं इसने आदिवासी और मछुआरा समुदायों को प्रभावित किया है और नदी पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाया है। डाउन टू अर्थ के रिचर्ड महापात्रा के अनुसार दुनिया भर में नदियों पर अब तक 62,000 बड़े बांध और लाखों छोटे अवरोध बनाए जा चुके हैं। डेम रिमूवल यूरोप (डीआरई) के अनुसार, 2024 में 23 देशों ने 542 बाधाओं को हटाया है। नदियों के स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए बांधों और अवरोधों को हटाना अब एक तेजी से स्वीकार किया जा रहा उपाय बन चुका है, और इसमें खास तौर पर यूरोप और उत्तर अमेरिका में तेजी आई है, जहां पुराने, असुरक्षित, अनुपयोगी या आर्थिक रूप से अलाभकारी बांधों को हटाया जा रहा है।नर्मदा नदी आज मानवीय हस्तक्षेप, जलवायु परिवर्तन और अंधाधुंध दोहन के कारण गहरे पारिस्थितिकी संकट से जूझ रही है। नर्मदा घाटी में 30 बड़े बांध प्रस्तावित है। इसमें से कई बड़े बांध बनाए जा चुके हैं। अतरू उन सभी बांधों का नर्मदा नदी पर पडने वाले उसके वहन क्षमता और संचयी प्रभावों (कम्यूलेटिव ईम्पेकट) का एकत्रित अध्ययन पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक है। अतरू नर्मदा घाटी में निर्मित हुए बांधों के प्रभाव को एकत्रित अध्ययन के बाद ही कोई अन्य बांध बनाने पर विचार होना चाहिए। मछली जलीय पर्यावरण पर आश्रित जलीय जीव है तथा जलचर पर्यावरण को संतुलित रखने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस पानी में मछली नहीं हो तो निश्चित ही उस पानी की जल जैविक स्थिति सामान्य नहीं है। वैज्ञानिकों द्वारा मछली को जीवन सूचक (बायोइंडीकेटर) माना गया है। अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नर्मदा नदी पर गत दशकों में अलग– अलग बांध बनने के बाद इसके पानी का प्राकृतिक बहाव में रुकावट आई है, जिससे मध्यप्रदेश की राजकीय मछली महाशीर के अस्तित्व पर संकट आ गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने भारत में नदियों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य मुख्य रूप से जैसे नदी प्रदूषण रोकना, अवैध खनन नियंत्रित करना, अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना और जलधाराओं को अविरल बनाए रखना है। भारत में नदियों की रक्षा के लिए प्रदूषण नियंत्रण, प्रवाह संरक्षण, तट प्रबंधन, जनभागीदारी और कानूनी उपाय आवश्यक हैं। सरकार ने नमामि गंगे जैसी योजनाएं शुरू की हैं, परंतु सफलता तभी मिलेगी जब स्थानीय समुदाय, सरकार, उद्योग और नागरिक मिलकर नदी को संसाधन नहीं, बल्कि जीवन के रूप में संरक्षित करें। नदियां केवल पानी का स्रोत नहीं हैं, वे सभ्यता, संस्कृति, कृषि, जैव विविधता और करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार हैं। इसलिए नदी संरक्षण को केवल प्रदूषण नियंत्रण या नदी–सफाई के अभियानों तक सीमित नहीं किया जा सकता। नदी की वास्तविक सेहत उसके अविरल प्रवाह, निर्मल जल, प्राकृतिक जलधाराओं, भूजल पुनर्भरण, जैव विविधता और उससे जुड़े समुदायों के अधिकारों से तय होती है। बड़ी नदियों को बचाने के लिए उनकी छोटी सहायक नदियों, जलधाराओं और जलग्रहण क्षेत्रों को बचाना होगा।

मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ ने बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए समर्पित चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया'

'लखनऊ, सितंबर 28, 2026।' मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, लखनऊ ने बच्चों के विकास, व्यवहार और न्यूरोलॉजी से जुड़ी परेशानियों के लिए समर्पित चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया है। इस सेंटर का मकसद बच्चों में किसी भी तरह की परेशानी को समय पर पहचानना, उसकी सही जांच करना और जरूरत के हिसाब से इलाज और थेरेपी शुरू करना है। इस सेंटर में बच्चों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग विशेषज्ञ मिलकर काम करेंगे। सेंटर का नेतृत्व डॉ. एम.यू. हसन, डायरेक्टर एवं एचओडी, पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजीय डॉ. अंकिता गर्ग, कंसल्टेंट, चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकियाट्री और डॉ. देविना सिंह, कंसल्टेंट, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, लखनऊ करेंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक 2 से 4 साल की उम्र में बच्चों का देर से बोलना या भाषा सीखने में परेशानी होना माता पिता के लिए चिंता की बात हो सकती है। कई बार इसका कारण ऑटिज्म, सुनने में परेशानी या बच्चे के विकास से जुड़ी कोई दूसरी समस्या हो सकती है। इसलिए अगर बच्चे के विकास में कोई देरी दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय समय पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में 1 से 18 साल तक के बच्चों का इलाज और देखभाल की जाएगी। यहां ऑटिज्म, एडीएचडी, बोलने में देरी, चलने या दूसरी गतिविधियां सीखने में देरी, पढ़ाई में परेशानी, चीजों को महसूस करने और समझने में दिक्कत, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, बौद्धिक विकास से जुड़ी समस्याएं, लोगों से बातचीत करने में परेशानी, मिर्गी और व्यवहार से जुड़ी समस्याओं के लिए मदद मिलेगी। सेंटर की शुरुआत पर डॉ. एम.यू. हसन, डायरेक्टर एवं एचओडी, पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, लखनऊ, ने कहा, ""मैक्स हॉस्पिटल, लखनऊ में हमारा मानना है कि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है और समय पर सही मदद मिलने से बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण और लंबे समय तक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हमारा इलाज केवल थेरेपी सेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परिवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी अलग–अलग विशेषज्ञों की टीम माता–पिता के साथ मिलकर बच्चे की खूबियों, चुनौतियों और जरूरतों को समझती है और उसके लिए व्यक्तिगत आधार पर तैयार की गई थेरेपी योजना बनाती है, जिससे बच्चे को लगातार और बेहतर प्रगति करने में मदद मिल सके।" डॉ. अंकिता गर्ग, कंसल्टेंट, चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकियाट्री, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, लखनऊ, ने कहा, "बच्चे के शुरुआती साल उसके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अगर बच्चा देर से बोल रहा है, आंखों में देखकर बात नहीं करता, नाम पुकारने पर ध्यान नहीं देता या उसके व्यवहार और ध्यान को लेकर कोई परेशानी दिखती है तो माता पिता को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही समय पर जांच और मदद मिलने से बच्चे को काफी फायदा हो सकता है। एक ही सेंटर पर अलग अलग विशेषज्ञों की मदद मिलने से परिवारों के लिए भी सही इलाज तक पहुंच आसान होगी।" बच्चे के विकास में किसी परेशानी की जितनी जल्दी पहचान हो, उतनी जल्दी उसकी मदद शुरू की जा सकती है। खासकर शुरुआती उम्र में फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और व्यवहार से जुड़ी थेरेपी से बच्चे को चलने फिरने, बोलने, सीखने, दूसरों के साथ घुलने मिलने और रोजमर्रा के काम करने में मदद मिल सकती है। इसलिए छोटे बच्चों के विकास पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर समय पर विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। डॉ. देविना सिंह, कंसल्टेंट, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, लखनऊ ने कहा, "बच्चे का सही विकास उसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। विकास से जुड़ी परेशानी सिर्फ एक चीज तक सीमित नहीं होती। इसका असर बच्चे के बोलने, सीखने, चलने, व्यवहार और दूसरों के साथ बातचीत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में बच्चे को एक से ज्यादा विशेषज्ञों की मदद की जरूरत हो सकती है। न्यूरोलॉजी की जांच और इलाज के साथ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्यवहार से जुड़ी थेरेपी, फिजियोथेरेपी और सही पोषण पर ध्यान देने से बच्चे के विकास में सुधार लाने में मदद मिल सकती है। अलग अलग विशेषज्ञों का साथ मिलकर काम करना बच्चे की जरूरत को बेहतर तरीके से समझने और उसके लिए सही इलाज तय करने में मदद करता है।" चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यानी एबीए थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियरल थेरेपी, अर्ली इंटरवेंशन, फिजियोथेरेपी और संसेरी इंटीग्रेशन थेरेपी की सुविधा एक ही जगह मिलेगी। हर बच्चे के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से इलाज और थेरेपी की योजना बनाई जाएगी। मैक्स अस्पताल, लखनऊ का यह सेंटर बच्चों को जरूरी चीजें सीखने, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के काम खुद करने और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। इसके साथ ही माता पिता को भी बच्चे को समझने और उसकी बेहतर देखभाल करने में मदद दी जाएगी। सेंटर का मकसद बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य, सही पोषण, परिवार का प्यार और देखभाल, सुरक्षा और शुरुआती उम्र में सीखने के बेहतर मौके देना है।

दुकान के सामने सो रहे व्यक्ति की ठोस वस्तु से मारकर हत्या

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में सिकरारा थाना क्षेत्र के गोदाम चौराहे के पास रविवार देर रात दुकान के सामने सो रहे एक व्यक्ति की अज्ञात लोगों ने ठोस वस्तु से वार कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

मृतक की पहचान भभौरी गांव निवासी उदयराज यादव (50) के रूप में हुई है। बताया गया कि उदयराज प्रतिदिन की तरह गोदाम चौराहे के पास स्थित एक दुकान के सामने सोता था। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। रविवार रात किसी समय अज्ञात व्यक्ति ने उसके सिर पर किसी भारी या ठोस वस्तु से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही घटना के कारणों और हमलावरों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है।

परिजनों के संबंध में बताया गया कि मृतक चार भाइयों में से एक था। उसके एक भाई की पहले ही हत्या हो चुकी है, जबकि दूसरा भाई मुंबई में रहकर काम करता है। एक भाई काफी समय से लापता है। मृतक की मां भी कुछ दिन पहले ही कहीं से वापस लौटी हैं। पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।इस संबंध में सोमवार को जानकारी देते हुए

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि 28 सितंबर को थाना सिकरारा अंतर्गत गोदाम चौराहे पर उदयराज नामक व्यक्ति जो भभौरी के रहने वाले है, उसके सर में चोट कारित करने से मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट द्वारा मौके से साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। परिजनों और आसपास के लोगों से वार्ता के क्रम में यह जानकारी मिली है कि मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त थे और यहीं पर यह निवास करते थे। प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में घटना के अनावरण के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। हत्या किन परिस्थितियों और किन कारणों से हुई, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से छानबीन कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।

संक्षिप्त खबरें

साहित्यकारों और कलाकारों को मिला सम्मान

लखनऊ, (संवाददाता)। मां दुर्गा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था की ओर से शुक्रवार को यूपी प्रेस क्लब में सम्मान समारोह हुआ। इस दौरान साहित्य, कला एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान प्रदान किए गए। साहित्य के क्षेत्र में ज्योत्सना सिंह को अरुण साहित्य सम्मान, कला एवं रंगकर्म के क्षेत्र में अनुपम बिसारिया को और पत्रकारिता के क्षेत्र में पंकज तिवारी को सम्मानित किया गया। संस्था के संरक्षक सर्वेश अस्थाना ने अतिथियों और सम्मानित व्यक्तित्वों का अभिनंदन किया। अलका अस्थाना ने अपने पिता की स्मृतियों और उनके व्यक्तित्व से जुड़े संस्मरण साझा किए। मुख्य अतिथि आकाशवाणी की निदेशक सुमोना पांडेय, अतिविशिष्ट अतिथि प्रो. सुरेंद्र विक्रम और पं. आदित्य द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉ. दिनेश चंद्र अवस्थी उपस्थित रहे।

शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)।। सुशान्त गोल्फ सिटी थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ संबंध बनाने, मारपीट करने, गाली–गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 24 सितंबर 2026 को पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपी उसके साथ रह रहा था और शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाता था। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट और गाली–गलौज की तथा जान से मारने की धमकी भी दी ।तहरीर के आधार पर सुशान्त गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 644ध्2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 89, 318(4), 115(2), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देश पर दो टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों तथा स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से आरोपी की तलाश की और आतिफ खान को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।गिरफ्तार आरोपी की पहचान आतिफ खान पुत्र एजाजुद्दीन उर्फ संजू, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी मोहल्ला नाजिरपुरा, थाना नगर कोतवाली, जनपद बहराइच के रूप में हुई है।

मोहनलालगंज पुलिस ने वारंटी रितुराज को किया गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। मोहनलालगंज थाना पुलिस ने न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस के अनुसार न्यायालय लखनऊ द्वारा वाद संख्या 419ध्2021 और मुकदमा अपराध संख्या 074ध्2017 से संबंधित वारंट जारी किया गया था। वारंट की तामील और संबंधित अभियुक्त की तलाश के लिए पुलिस टीम ने 25 सितंबर को उसके पते पर दबिश दी ।दबिश के दौरान वारंटी रितुराज पुत्र सत्यनारायण, निवासी ग्राम डेहवा, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ, उम्र करीब 30 वर्ष, अपने घर पर मौजूद मिला। पुलिस टीम ने उसे न्यायालय के आदेश से अवगत कराते हुए गिरफ्तार कर लिया।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियुक्त दिनेश को एक वर्ष दो माह सात दिन की सजा

लखनऊ, (संवाददाता)। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत लखनऊ पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते सैरपुर थाने से संबंधित एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष दो माह सात दिन के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, लखनऊ ने 22 सितंबर 2026 को यह फैसला सुनाया ।पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों को न्यायालय से अधिकाधिक सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। पुलिस आयुक्त और संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के निर्देशन तथा पुलिस उपायुक्त उत्तरी के पर्यवेक्षण में सैरपुर थाना पुलिस और अभियोजन विभाग ने मामले में लगातार पैरवी की ।मामला मुकदमा अपराध संख्या 76/2025 से संबंधित है।

बैंक कर्मी अफसर की हत्या में नया मोड़, बीमा और बैंक में फंसी रकम के लिए करानी पड़ी एफआईआर

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ के गोमतीनगर के मिठाई वाला चौराहे के पास 20 अगस्त को पत्नी दिव्या मिश्रा और हुसड़िया चौराहा स्थित घर में बहन तूलिका की हत्या के

बाद आत्महत्या करने वाले मानस बाजपेयी पर दर्ज हुई एफ आई आर के मामले में नया तथ्य सामने आया है। पता चला है कि दिव्या का बीमा और बैंक में फंसी रकम बिना एफआईआर के नहीं निकाली जा सकती थी। यही वजह है कि पुलिस ने मृतक मानस पर हत्या की एफआईआर दर्ज की है। दिव्या मिश्रा आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थीं। दिव्या की हत्या भी बैंक के ठीक सामने हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक प्रबंधन ने डीसीपी पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा से संपर्क किया था। प्रबंधन ने कहा था कि बीमा और अन्य धनराशि के लिए प्राथमिकी दर्ज कराना आवश्यक है। इसके बाद ही दिव्या के पिता सतीश चंद्र मिश्रा ने गोमतीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी के मुताविक पुलिस को मानस के शव के पास से तीन असलहे मिले थे। बरामद असलहों को नष्ट कराया जाएगा। बिना एफआईआर के असलहों को नष्ट नहीं कराया जा सकता। इंस्पेक्टर का कहना है कि इस प्रकरण में आरोपी की मौत हो चुकी है। एफआईआर में अन्य किसी पर साजिश का आरोप नहीं लगाया गया है। ऐसे में इस प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट लगाई जाएगी। विवेचना पूरी कर अंतिम रिपोर्ट न्यायालय को भेजी जाएगी। उधर, इस मामले में मानस के रिश्तेदारों ने भी पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है। आवश्यक है। इसके बाद ही दिव्या के पिता सतीश चंद्र मिश्रा ने गोमतीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी के मुताविक पुलिस को मानस के शव के पास से तीन असलहे मिले थे।

सही समय पर सटीक जांच से सही उपचार संभव - डा0 रवि शंकर सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। श्री पैथालाजी एण्ड डायग्नोस्टिक सेण्टर के तृतीय स्थापना दिवस के अवसर पर सेण्टर के संचालक डा0 रवि षंकर सिंह एमडी पैथालाजी ने पत्रकारों को बताया कि जिले में कैसर और टीबी के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे है जो चिन्ता का विषय है। इसमें माउथ कैसर सर्वाधिक है जो कम आयु में ही गुटका, दोहरा और तम्बाकू खाने से हो रहा है। इसके बाद ब्रेस्ट कैसर की पीड़ितो की संख्या हैं इसका कारण जल्दी और देर से हो रही शादिया है। सालों इधर उधर इलाज के लिए दौड़ने पर जांच में यह यह बात प्रकाष आती है और स्थिति तब तक गंभीर हो चुकी हाती है। बच्चेदानी का कैसर भी महिलाओं में तेजी बढ़ जा रहा है। आये दिन हो रही जांच में यह बात प्रकाष में आ रही है। उन्होने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि सेण्टर में सभी टेस्ट हो जाय बाहर न भेजना पड़े और ऐसा संभव हो रहा है। उन्होने कहा कि प्रतिदिन चार पांच कैसर के केस मिल रहे है। समय पर जांच से कैस जीता जा सकता है। गरीब मरीजो के लिए विषेष सुविधा है। ष्षेका होने पर रोग छिपाये नहीं तुरन्त जांच करायें ।यहां की सभी जांच रिपोर्ट उसी दिन मरीज को उपलब्ध करा दी जाती है। इस अवसर पर सेटर पर निःषुल्क जांच शिविर लगाया गया जहां थायराइड, शुगर, हीमोग्लोबिन? सीबीसी सहित अन्य कई जांचे की गयी और करीब 200 लोग लाभान्वित हुए। डा0 एसके श्रीवास्तव, डा0 राकेष शुक्ला, रेडियोलाजिस्ट, पंकज सिंह, सच्चिदानन्द सिह, आकाष राम मिलन सहित अन्य स्टाफ के लोग मौजूद रहे।

रामनगरी पहुंची एनएसजी की टीम, राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

लखनऊ, (संवाददाता)। रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद के बीच नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) की टीम अयोध्या पहुंची है। टीम ने रामजन्मभूमि परिसर में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली। सूत्रों के अनुसार टीम की ओर से राम मंदिर की सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के समक्ष प्रेजेंटेशन भी दिया गया। अयोध्या में एनएसजी का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की तैयारी पहले से चल रही है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने मिल्कीपुर तहसील में करीब 26 हेक्टेयर यानी 65 एकड़ भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को एनएसजी क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य अयोध्या धाम और राम मंदिर की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाना है। इसी क्रम में एनएसजी टीम के अयोध्या पहुंचने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टीम ने राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, संभावित सुरक्षा चुनौतियों और आपात स्थिति में प्रतिक्रिया से जुड़े पहलुओं को समझने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की।

सेवा संकल्प अभियान के तहत स्मार्ट एवं स्वच्छ कॉलेज कैंपस प्रतियोगिता आयोजित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। गांधी स्मारक पीजी कॉलेज, समोधपुर, में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत स्मार्ट एवं स्वच्छ कॉलेज कैंपस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, अनुशासन तथा स्मार्ट कैंपस की अवधारणा के प्रति जागरूकता एवं रचनात्मक सोच विकसित करना रहा। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने प्रतिभाग करते हुए स्वच्छ एवं स्मार्ट महाविद्यालय परिसर के लिए विभिन्न नवीन विचार, सुझाव एवं मॉडल प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक–मुक्त परिसर, हरित परिसर, जल संरक्षण तथा डिजिटल सुविधाओं से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रणजीत कुमार पाण्डेय ने कहा कि स्वच्छ और स्मार्ट कैंपस केवल संस्थान की सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में जिम्मेदारी, अनुशासन और सामाजिक चेतना विकसित करने का माध्यम भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. लालमणि प्रजापति तथा सहसंयोजक श्री विकास कुमार यादव एवं श्री जितेंद्र कुमार रहे। संयोजक एवं सहसंयोजकों ने विद्यार्थियों को स्वच्छ, सुंदर एवं स्मार्ट महाविद्यालय परिसर के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर राकेश कुमार यादव, डॉ. लक्ष्मण सिंह, डॉ. नीलमणि सिंह, डॉ. अविनाश वर्मा, डॉ. अवधेश मिश्रा, डॉ. आलोक प्रताप सिंह बिसेन, डॉ. जितेंद्र सिंह आदि शिक्षकगण उपस्थित रहे। सभी ने विद्यार्थियों के रचनात्मक प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति निरंतर जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया।

यूपी की 403 विधानसभाओं में विकसित होंगे 4030 आंबेडकर प्रतिमा स्थल, 403 करोड़ रुपये जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में डॉ. बीआर आंबेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 403 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। डॉ. बीआर आंबेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना के तहत प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित 10–10 प्रतिमा स्थलों का विकास कराया जाएगा। इस तरह प्रथम चरण में कुल 4,030 प्रतिमा स्थलों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 22 सितंबर 2026 को निदेशालय स्तर से सभी जिलाधिकारियों के निवर्तन पर धनराशि आवंटित की गई है ।शासन के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में योजना के लिए 40,300 लाख रुपये यानी 403 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। प्रतिमा स्थलों के विकास पर औसतन 10 लाख रुपये प्रति स्थल खर्च किए जाने का अनुमान है, जबकि शासनादेश में किसी एक स्थल के विकास की अधिकतम लागत 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। वास्तविक खर्च स्थल की आवश्यकता और वहां प्रस्तावित कार्यों के आधार पर तय किया जाएगा ।योजना का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित डॉ. आंबेडकर और अन्य महान विभूतियों की प्रतिमाओं को सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानजनक स्वरूप प्रदान करना है।

दशलक्षण महापर्व के अंतिम दिन शहर के जैन मंदिरों में अभिषेक, शांतिधारा और धार्मिक अनुष्ठान

लखनऊ, (संवाददाता)। दशलक्षण महापर्व के दसवें और अंतिम दिन शुक्रवार को शहर के जैन मंदिरों में भक्ति व साधना का माहौल रहा। कहीं 108 स्वर्ण कलशों से भगवान का अभिषेक हुआ तो कहीं शांतिधारा और हवन के साथ पर्व की पूर्णाहुति की गई। श्रद्धालुओं ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना करते हुए मन, वचन और कर्म से विकारों का त्याग कर आत्मसंयम और पवित्रता अपनाने का संकल्प लिया। इस दौरान भगवान वासुपूज्य के मोक्ष कल्याणक और अनंत चतुर्दशी पर भगवान अनंतनाथ की विशेष पूजा भी हुई।

कूड़े के ढेर व बजबजाती नालियों पर बसा इंदिरानगर कालोनी

(दीपक श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ लखनऊ)

लखनऊ।राजधानी का प्रमुख आवासीय क्षेत्र इंदिरानगर इन दिनों कूड़े का ढेर,जलभराव और सफाई जैसी समस्याओं से जूझ रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि कई इलाकों में नालों की नियमित सफाई नहीं होने और सीवर व्यवस्था प्रभावित होने से बारिश के दौरान सड़कें पानी व कूड़े से भर जाती हैं।हाल में इंदिरानगर के लोगो ने समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया।स्थानीय लोगों के मुताबिक बारिश के समय यहां जलभराव व कूड़े की ढेर की स्थिति बनती है।इंदिरा नगर के सेक्टर मे कूड़ा,सीवर तथा जलभराव की समस्याओं का मुद्दा उठाया गया है। कई वार्ड के कुछ हिस्सों में भी नालों की सफाई और जलनिकासी को लेकर शिकायतें सामने आई हैं।इससे पहले इंदिरानगर के कई इलाकों में डोर–टू–डोर कूड़ा उठान प्रभावित होने की खबर सामने आई थी।पिछले कुछ दिनों पहले कूड़ा खाली प्लॉटों और नालों के आसपास जमा होने से सफाई व्यवस्था पर सवाल उठे थे।कूड़ा नालियों में पहुंचने से बारिश के दौरान जलभराव की समस्या बढ़ने की आशंका जताई गई थी।पिछले दिनों भारी बारिश के चलते जलभराव, कूड़े का ढेर, गंदगी दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद क्षेत्र के दूसरे हिस्सों में पुरानी समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग बनी हुई है।

जनसुनवाई के दौरान महिला एसओ तथा उनकी टीम मौके पर फरियादियों की समस्या की कर रही समाधा

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर मिशन शक्ति फेज–5 के तहत प्रतिदिन महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला महिला उप निरीक्षक सोनी, प्रिया व श्वेता राठौड़ के साथ जहां एक ओर मिशन शक्ति फेज 5 के तहत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को स्कूलों, चौराहा रेलवे स्टेशन बस स्टेशन सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर अपनी टीम के साथ जाकर महिलाओं बालिकाओं तथा छात्रों को जागरुक कर रही हैं।वहीं महिला थाना पर आने वाली दूर दराज से फरियादियों की समस्याओं का समाधान जनसुनवाई के दौरान अपनी सूझबूझ से भी कर रही हैं।जनसुनवाई के दौरान पति–पत्नी से मनमुटाव,छोटी–छोटी बातों में पति–पत्नी के बीच वाद विवाद उत्पन्न होना सहित कई जटिल समस्याओं का समाधान हुए कुछ ही समय में निपटारा कर रहे है।उनके साथ–साथ इन फरियादियों की समस्याओं का समाधान करने में महिला थाना पर तैनात महिला उप निरीक्षक सोनी, श्वेता राठौड़, प्रिया भी सहयोग करती हुई दिखाई दे रही थी।इन लोगो का कहना है कि केंद्र व राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता मे शामिल महिलाओ व बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के तहत सुरक्षा के उपाय व योजनाओं का बताना है। वही महिला थाना परिसर मे आने वाली महिला फरियादियों को त्वरित न्याय प्रदान करना है।

गड्डों में तब्दील शहर की सड़कें दुर्घटना को दे रही दावत

अयोध्या।शहर के अश्विनीपुरम कॉलोनी,लालबाग, फतेहगंज हनुमानगढ़ी के सामने से कसाबबाड़ा संपर्क मार्ग, हैदरगंज समेत कई प्रमुख सड़कों पर बड़े–बड़े गड्ढे राहगीरों के लिए मुसीबत बने हुए हैं।खासकर बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का पता नहीं चलता और दोपहिया वाहन चालक आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं।बताते चले कि अश्विनीपुरम कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर स्थित बड़ा गड्ढा विशेष रूप से खतरनाक दिखाई दे रहा है।स्थानीय लोगो का मानना है कि इस मार्ग से भोर से देर रात तक दोपहिया,चार पहिया व अन्य वाहनों का आवागमन रहता है।रात के समय अंधेरे में बाहर से आने वाले वाहन चालकों को गड्ढा दिखाई नहीं देने से हादसे का खतरा और बढ़ जाता है।और इस गड्ढे मे गिरकर चोटिल होते है।वहीं फतेहगंज हनुमानगढ़ी के सामने से कसाबबाड़ा जाने वाले मार्ग पर कई स्थानों से सड़क के पत्थर गायब होने के कारण गड्ढे है।बारिश और नाले का पानी सड़क पर बहने से स्थिति और खराब हो जाती है,और आए दिन दुर्घटना होती रहती है।स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की समस्या को लेकर कई बार स्थानीय पार्षद और नगर निगम से शिकायत की गई, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ।स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम व संबंधित विभाग से जल्द गड्ढों को भरवाकर सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।

टूटी सड़कें,कूड़े के ढेर और बजबजाती नालियां बनीं ककरहवा देवकाली की पहचान

अयोध्या।साकेत नगर वार्ड स्थित मोहल्ला ककरहवा देवकाली इन दिनों बदहाल सफाई व्यवस्था और जर्जर सड़कों की समस्या से जूझ रहा है।यहाँ जगह–जगह लगे कूड़े के ढेर और बजबजाती नालियां स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं।एक ओर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की ओर से टाइफाइड,डेंगू और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को साफ–सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है,वहीं दूसरी ओर ककरहवा देवकाली में गंदगी और जलभराव जैसी स्थिति इन अभियानों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रहे है।नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से उनमें गंदगी जमा है और दुर्गंध से लोगों का गुजरना मुश्किल हो रहा है।स्थानीय लोगो का कहना है कि इस मोहल्ले की कई सड़कें भी टूट चुकी हैं।नालियों को ढकने के लिए रखे गए पत्थर कई स्थानों से गायब हैं। जिससे खुले नाले हादसे का कारण बन सकते हैं।बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को यहां से गुजरते समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।ककरहवा देवकाली में स्कूल और मंदिर भी स्थित हैं।ऐसे में छात्रों और श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी रहती है। मोहल्ले में फैली गंदगी और नालियों से उठती दुर्गंध के बीच लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम के मेयर, नगर आयुक्त व स्थानीय पार्षद मंसूर अली से इस समस्या की ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद संबंधित विभाग की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी।स्थानीय लोगों ने मोहल्ले में नियमित सफाई, नालियों की मरम्मत, गायब पत्थरों को दोबारा लगाए जाने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग की है। लोगों का कहना है कि बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान तभी प्रभावी होगा, जब मोहल्लों में सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त हो।

संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के बजाय तथ्यों का विपक्ष करे सम्मान – गिरीश पति त्रिपाठी

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।सर्किट हाउस सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर चुनावी पराजय की खीझ में संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने और जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक कमजोरियों पर आत्ममंथन करना चाहिए। चुनाव हारने के बाद निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना समस्या का समाधान नहीं है।महापौर ने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर निर्वाचन आयोग स्थिति स्पष्ट कर चुका है।मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा दोनों निर्वाचन आयुक्तों की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि एसआईआर समेत प्रमुख निर्णय आयोग की सहमति से लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 24 जून 2025 के मूल आदेश से लेकर विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू प्रक्रिया तक निर्णय आयोग की सहमति से लिए गए हैं। उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया को कानूनी रूप से वैध माना है।उन्होंने कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र को लेकर उठे विवाद पर कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह पत्र आयोग की किसी नीति अथवा एसआईआर से संबंधित नहीं था, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी से जुड़े प्रशासनिक विषय तक सीमित था।इसी प्रकार फॉर्म–6 को लेकर भी विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आयोग के अनुसार गैर–एसआईआर अवधि में पूर्व निर्धारित नियम ही लागू हैं और प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।महापौर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुराने बयानों का उल्लेख करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है। उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर आरोप लगाने और न्याय पालिका पर दबाव होने संबंधी बयानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विदेशों में भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर दिए गए बयानों से देश की संस्थाओं की छवि प्रभावित करने का प्रयास किया गया।उन्होंने राफेल सौदे का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले में कांग्रेस की ओर से "चौकीदार चोर है" जैसे राजनीतिक आरोप लगाए गए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या को लेकर राहुल गांधी को बाद में अदालत में खेद व्यक्त करना पड़ा था।महापौर ने कहा कि राजनीतिक आरोपों और न्यायिक निष्कर्षों के बीच अंतर रखा जाना चाहिए।

महापौर ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सैन्य अभियानों पर भी राजनीतिक बयानबाजी की गई।उन्होंने तवांग झड़प का उल्लेख करते हुए कहा कि राहुल गांधी द्वारा भारतीय जवानों की पिटाई किए जाने संबंधी बयान पर सेना और सरकार ने आपत्ति जताई थी।उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर राजनीतिक विमर्श तथ्यों और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विपक्ष कभी ईवीएम, कभी निर्वाचन आयोग, कभी सुप्रीम कोर्ट और कभी अन्य संस्थाओं पर सवाल उठाकर अपनी राजनीतिक विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास करता है। लोकतंत्र में संस्थाओं की आलोचना का अधिकार है,लेकिन आरोप तथ्यों पर आधारित होने चाहिए,तथ्यों के आधार पर बात रखे विपक्ष रोली सिंह जिला पंचायत प्रशासक रोली सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची और एसआईआर जैसे विषयों पर राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप के बजाय आधिकारिक तथ्यों को जनता के सामने रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग अपना स्पष्टीकरण दे चुका है और लोकतंत्र में मतदाता की भागीदारी तथा निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों को संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने से पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया प्रभारी अमित कुमार मिश्र मौजूद रहे।

’आयुर्वेद दिवस सप्ताह में सेवाभावी चिकित्सकों का हुआ सम्मान’

‘ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव’

‘शाहजहाँपुर’ भारत सरकार की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में ग्यारहवें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के जनजागरण सप्ताह के क्रम में इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय परिसर स्थित रेडक्रॉस कार्यालय में आयुर्वेद चिकित्सकों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ मुकेश कुमार एवं जिला चिकित्सालय के आयुष विभाग के आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेंद्र कुशवाहा को आयुर्वेद चिकित्सा एवं जनसेवा में योगदान के लिए रेडक्रॉस का मेडल पहनाकर, शाल ओढ़ाकर, प्रशस्ति पत्र एवं मिष्ठान प्रदान कर सम्मानित किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉ विजय जौहरी ने कहा कि मानव सेवा एवं जनस्वास्थ्य रेडक्रॉस की मूल भावना है। सेवाभावी चिकित्सकों का सम्मान उनका मनोबल बढ़ाने के साथ ही उन्हें भविष्य में और अधिक निष्ठा से जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। आयुर्वेद दिवस सप्ताह का उद्देश्य आयुर्वेद के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना और सरकारी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाओं को जन–जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से जनपद में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रचार–प्रसार एवं जनसेवा की गतिविधियों को और गति मिलेगी। उन्होंने जिला प्रशासन तथा क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय का विशेष आभार व्यक्त किया, जिन्होंने रेड क्रॉस को इस अभियान में सहभागी बनाकर सेवा का अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर संजय अग्रवाल, राजीव शर्मा, डॉ एस.पी. कौशल, डॉ हितेश गुप्ता, डॉ रवि सक्सेना, डॉ आर.पी. सक्सेना, बृजेश गुप्ता, अमरीश सक्सेना सहित उपस्थित रहे। अंत में डॉ विजय जौहरी ने सभी चिकित्सकों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।

10 जिलों में स्कूल बंद, गोरखपुर–बस्ती मंडल में 12वीं तक छुट्टी, शाहजहांपुर में अलग आदेश

गोरखपुर, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट के बीच बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए 10 जिलों में स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। गोरखपुर और बस्ती मंडल के पांच जिलों गोरखपुर, महराजगंज, बस्ती, संतकबीर नगर और सिद्धार्थनगर में विद्यालयों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें संतकबीर नगर में कक्षा आठवीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, जबकि अन्य जिलों में 12वीं तक के विद्यालयों में अवकाश रहेगा। लगातार बारिश और मौसम की प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए

गोरखपुर, महराजगंज, बस्ती और सिद्धार्थनगर में कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यालय बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। संतकबीर नगर में कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलजमाव और आवागमन की समस्या सामने आ रही है। ऐसे में प्रशासन ने विद्यालय आने वाले बच्चों को किसी तरह की परेशानी से बचाने के लिए अवकाश घोषित किया है। संबंधित शिक्षा अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही में भी बारिश के मद्देनजर स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जौनपुर में मौसम विभाग के रेड अलर्ट और लगातार हो रही अतिवृष्टि के कारण 26 सितंबर को कक्षा एक से आठवीं तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। आदेश परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के स्कूलों पर लागू है। मिर्जापुर में कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। भदोही में भी 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहां मौसम विभाग ने 27 सितंबर तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि भदोही में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों को जरूरी विभागीय कार्यों के लिए स्कूल पहुंचना होगा। वाराणसी में भी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भोलेंद्र प्रताप सिंह ने विद्यालय बंद रखने का निर्देश जारी किया है।

जीडीए के सामने फिर ट्रांसफॉर्मर से तेल चोरी

गोरखपुर, (संवाददाता)। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के सामने देवरिया बाईपास के किनारे लगे 400 केवीए के ट्रांसफॉर्मर से बृहस्पतिवार देर रात फिर तेल चोरी हो गया। चार महीने के भीतर इस ट्रांसफॉर्मर और आसपास लगे ट्रांसफॉर्मरों से तेल चोरी की यह चौथी घटना है। खास बात यह है कि ताजा घटना के समय बिजली की आपूर्ति चल रही थी। सड़क किनारे दिन–रात आवाजाही वाले स्थान पर हुई चोरी ने बिजली निगम के साथ पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े किए हैं। देवरिया बाईपास (फोरलेन) पर जीडीए के सामने 400–400 केवीए क्षमता के दो ट्रांसफॉर्मर अगल–बगल लगे हैं। यहीं से सामने स्थित अश्वमेघनगर कॉलोनी में बिजली की आपूर्ति होती है। करीब चार महीने पहले एक ट्रांसफॉर्मर से तेल चोरी हुआ था। सुबह टहलने निकले लोगों ने इसकी जानकारी बिजली निगम के अभियंताओं को दी, जिसके बाद आपूर्ति बंद कराई गई। समय रहते आपूर्ति बंद होने से ट्रांसफॉर्मर जलने से बच गया।

प्रसव के बाद 26 वर्षीय महिला की मौत, निजी नर्सिंग होम पर आरोप

अयोध्या।तारुन थाना क्षेत्र के गुरौली ग्राम पंचायत के मजरा सराय सागर निवासी 26 वर्षीय अनुराधा पत्नी विश्वास यादव की प्रसव के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई।परिजनों ने तारुन बाजार स्थित एक निजी नर्सिंग होम पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है।मृतका के परिजनों के मुताबिक अनुराधा को 21 सितंबर को तारुन बाजार स्थित एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था,जहां ऑपरेशन के जरिए प्रसव कराया गया। प्रसव के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी।परिजनों को खून और प्लेटलेट्स की कमी बताए जाने पर उसके पति को इसकी व्यवस्था के लिए मेडिकल कॉलेज दर्शननगर भेजा गया। आरोप है कि इसी दौरान अनुराधा को नर्सिंग होम से डिस्चार्ज कर दिया गया।इसके बाद परिजन उसे दर्शननगर ले गए।जहां से हालत गंभीर होने पर लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।वहां इलाज के दौरान अनुराधा की मौत हो गई।सोमवार को परिजन शव लेकर तारुन स्थित नर्सिंग होम पहुंचे,जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।सीएमओ ने इस मामले मे स्वास्थ्य विभाग की टीम से मामले की जांच कराने की बात कही है।फिलहाल परिजनों की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है।मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही जा रही है।

नकली पुलिस कर्मी बनकर लोगो से वसूली करने वाले शातिर युवक गिरफ्तार

अयोध्या।कोतवाली अयोध्या पुलिस ने पुलिस आरक्षी की वर्दी पहनकर रेलवे स्टेशन व आसपास के बाजार में व्यापारियों और आम लोगों पर रौब गांठकर वसूली करने वाले शातिर युवक को गिरफ्तार किया।पुलिस ने आरोपी के पास से पुलिस की पूरी वर्दी,फर्जी पुलिस पहचान पत्र,7,500 रुपये नकद और एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अयोध्या पंकज सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए

गए आरोपी सत्यम मिश्रा (26) निवासी मिश्रौलिया, थाना कलवारी, बस्ती इधर कुछ दिनों से खुद को पुलिस कर्मी बताकर रेलवे स्टेशन के अलावाआसपास दुकानदारों और आम लोगों को जांच के नाम पर डराता–धमकाता था और रुपये व सामान वसूलता था।आरोप है कि उसने पुलिसिया रौब दिखाकर एक व्यक्ति का मोबाइल फोन भी ले लिया था।बताया कि इसकी सूचना मिलने पर कोतवाली अयोध्या पुलिस ने रविवार को परिक्रमा मार्ग स्थित बड़ी छावनी मोड़ से उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया। पहले तो उसने अपने को पुलिसकर्मी बताया लेकिन कड़ाई से पूछताछ में नकली पुलिस कर्मी बताया। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से यूपी पुलिस आरक्षी की नेमप्लेट,बेल्ट, कैप,बूट व मोनोग्राम सहित पूरी वर्दी, पहचान पत्र, नकदी और मोबाइल बरामद हुए।इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अयोध्या पंकज सिंह के अलावा उप निरीक्षक राणा दिग्विजय सिंह,पवन कुमार समेत अन्य पुलिस कर्मी शामिल रहे।

कैंट पुलिस ने 24 घण्टे के अंदर लूट का खुलासा कर चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

अयोध्या।कैंट पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट का खुलासा कर इसमें शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट संदीप सिंह ने बताया कि कैंट पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए रुपये,मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त टाटा टिगोर कार बरामद किया।बताया कि सहादतगंज निवासी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कार सवार चार अज्ञात लोगों ने उसके साथ मारपीट कर जेब में रखे रुपये और मोबाइल फोन छीन लिया तथा जान से मारने की धमकी दी।इस मामले में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।बताया कि रविवार को अब्बू सराय सर्विस लेन रेलवे क्रॉसिंग की ओर खाली प्लॉट से इन चारो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अमन सिंह, राजन सिंह, कमलदीप तिवारी और हर्ष पाण्डेय के रुप मे हुई।पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों में अमन, राजन और हर्ष के खिलाफ अंबेडकरनगर के भीटी थाने में पहले से मुकदमे दर्ज हैं।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक **देश की उपासना**

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।